



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 माघ 1940 (श०)

(सं० पटना 198) पटना, बुधवार, 6 फरवरी 2019

सं० 7/स्था०-1-09-03/2012-12453/सा०प्र०
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

17 सितम्बर 2018

विषय:— बिहार उच्च न्यायिक सेवा (जिला न्यायाधीश कोटि) के स्वीकृत संवर्गीय पद बल के आधार पर प्रवर कोटि एवं अधिकाल वेतनमान में पदों का सम्परिवर्तन की स्वीकृति।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पीटिशन (सिविल) संख्या-1022/89, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा संघ एवं अन्य में दिनांक 21.03.2002 एवं 25.11.2002 को पारित आदेश के आलोक में बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के वेतन पुनरीक्षण संबंधी आदेश वित्त विभागीय संकल्प संख्या-1915 दिनांक 12.03.2003 द्वारा निर्गत किया जा चुका है। तत्संबंधी शुद्धि पत्र वित्त विभाग के ज्ञापांक-2733 दिनांक 03.04.2003 द्वारा निर्गत किया जा चुका है।

2. उपर्युक्त निर्गत संकल्प में जिला एवं सत्र न्यायाधीशों की कोटि में प्रवर कोटि एवं अधिकाल वेतनमान में पदों की संख्या एवं प्रोन्नति की अनुमान्यता की शर्तें निर्धारित नहीं की गयी थी। अतः जिला न्यायाधीश कोटि में प्रवर कोटि एवं अधिकाल वेतनमान में प्रोन्नति अनुमान्य करने हेतु प्रवर कोटि तथा अधिकाल वेतनमान में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पदों की संख्या एवं शर्तों के निर्धारण का विषय राज्य सरकार के विचाराधीन था।

3. सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार निश्चित अवधि के लिए कुल स्वीकृत बल 550 (पाँच सौ पचास) पदों में से पूर्व में स्वीकृत 287 (दो सौ सतासी) पद, जिसमें स्थायी 140 (एक सौ चालीस) एवं अस्थायी 147 (एक सैंतालीस) पद को विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-9649 दिनांक 26.08.2011 द्वारा सम्परिवर्तन के उपरांत वर्तमान में सृजित 262 (दो सौ बासठ, जिसमें 16 पद स्थायी या अस्थायी पद का उल्लेख नहीं है) पद के फलस्वरूप शेष 263 (दो सौ तिरसठ) पद में से स्वीकृत प्रतिशत 25% प्रवर कोटि तथा 10% अधिकाल वेतनमान के स्थायी एवं अस्थायी पदों के आधार पर संसूचित 410 (चार सौ दस) पद स्थायी तथा 140 (एक सौ चालीस) अस्थायी पद को सम्परिवर्तन निम्नरूपेण स्वीकृत करने का निर्णय लिया है:—

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	कुल स्थायी पदों (16 पद स्थायी या अस्थायी पद का उल्लेख नहीं है) की संख्या	कुल अस्थायी पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1	उच्च न्यायिक सेवा संवर्ग (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/जिला एवं सत्र न्यायाधीश का प्रवेश बिन्दु)	51550-63070	267	91

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान	कुल स्थायी पदों (16 पद स्थायी या अस्थायी पद का उल्लेख नहीं है) की संख्या	कुल अस्थायी पदों की संख्या
1	2	3	4	5
2	जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रवर कोटि)	57700-70290	102	35
3	जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अधिकाल वेतनमान)	70290-76450	41	14
			410	140

4. जिला न्यायाधीश कोटि में प्रवर कोटि वेतनमान एवं अधिकाल वेतनमान में प्रोन्नति हेतु निम्नांकित शर्तों को निर्धारित करने का प्रस्ताव है:-

- (I) प्रवर कोटि वेतनमान में प्रोन्नति के लिए जिला न्यायाधीशों की कोटि में न्यूनतम पाँच वर्षों की लगातार संतोषप्रद सेवा तथा अधिकाल वेतनमान में प्रोन्नति के लिए प्रवर कोटि जिला न्यायाधीश के पद पर न्यूनतम तीन वर्षों की संतोषप्रद सेवा का पूरा होना अनिवार्य होगा।
- (II) जिला न्यायाधीश कोटि के न्यायिक पदाधिकारियों के लिए उपर्युक्त प्रवर कोटि/अधिकाल वेतनमान में प्रोन्नति कार्यात्मक प्रोन्नति होगी तथा प्रोन्नति के लिए विहित मानक यथा विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता, उच्चतर योग्यता आदि, जो भर्ती नियमावली में विहित है, का पूरा होना आवश्यक होगा।
- (III) चूँकि ये प्रोन्नतियाँ कार्यात्मक प्रकृति की होगी, अतः प्रोन्नति के पदों का निर्धारण उच्च न्यायालय, पटना द्वारा किया जायेगा।
- (IV) उपर्युक्त प्रवर कोटि वेतनमान/अधिकाल वेतनमान स्वतः देय नहीं होगा, बल्कि उच्च न्यायालय, पटना द्वारा गठित वरिष्ठ न्यायाधीशों की समिति द्वारा संबंधित पदाधिकारियों के कार्यों के मूल्यांकन एवं योग्यता-सह-वरीयता के आधार पर की गयी अनुशंसा के आलोक में स्वीकृत किया जायेगा।
- (V) प्रवर कोटि वेतनमान/अधिकाल वेतनमान में प्रोन्नति हेतु संकल्प निर्गत होने के पश्चात् उच्च न्यायालय, पटना द्वारा स्थायी एवं अस्थायी पदों के विरुद्ध कार्यात्मक पदों को चिन्हित कर ही प्रोन्नति की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
- (VI) प्रवर कोटि वेतनमान/अधिकाल वेतनमान कार्यात्मक प्रोन्नति होने के कारण, प्रोन्नति इस सम्पत्तिवर्तन आदेश के निर्गत होने की तिथि से ही किया जायेगा।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति सभी संबंधित विभागों/विभागाध्यक्षों/ महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश/बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
शिवमहादेव प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 198-571+200-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>